

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 एलजी के भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाए

06 अंतरिक्ष में कामयाबी के कदम

08 प्रयागराज भगदड़: प्रशासनिक लापरवाही या भक्तों का उन्माद

परिवहन विभाग के झूलझूली वाहन जांच शाखा की कार्यशैली पर होनी चाहिए निष्पक्ष जांच

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों द्वारा लगातार उठाए जाने वाली शिकायतों पर वहां के अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्यरत निजी कंपनी के स्टाफ की कार्यशैली की जांच की मांग जोर उठा रही है। इस जांच की मांग उठाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, आइए उनमें से कुछ कारण जानते हैं।

1. वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक अपॉइंटमेंट आम वाहन मालिकों द्वारा प्राप्त करना असंभव है जब की कई अन्य अपनी इच्छा के अनुसार मुंह मागे दाम प्राप्त कर गारंटी के साथ अपॉइंटमेंट उपलब्ध करके दे देते हैं। वाहन मालिकों का कहना है की ऐसा कृत्य अंदरूनी अधिकारियों, कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं।

2. वाहन मालिकों की दूसरी शिकायत है की झूलझूली वाहन जांच शाखा में आम वाहन मालिकों के वाहनों की जांच सिर्फ प्राप्त अपॉइंटमेंट तारीख पर ही की जाती है पर अंदर ही अंदर अपने परिचितों के वाहन की जांच

प्राप्त अपॉइंटमेंट से पहले ही कर दी जाती है, 3. वाहन मालिकों की शिकायत है की अन्दर के अधिकारी और कर्मचारी वाहन की वहां लगी हुई ऑटोमेटिक मशीन से जांच करवाए बिना भी कई वाहनों को जांच प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं,

4. वाहन मालिकों की शिकायत है की झूलझूली वाहन जांच शाखा के बाहर उपस्थित मध्यस्थता करने वालों के माध्यम से जांच के लिए गया वाहन 100 प्रतिशत जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करके आयेगा पर आम वाहन मालिकों के वाहन बिलकुल कसौटी पर खरे होने के बावजूद फेल कर दिए जाते हैं,

5. झूलझूली वाहन जांच शाखा क्षेत्र में वाहन मालिकों और उनके वाहनों की सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है और अंदरूनी अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं करते।

झूलझूली वाहन जांच शाखा में कार्यरत सभी सरकारी, विभागीय और निजी कर्मचारियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच एजेंसी द्वारा जांच।



टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathiasanjanjaybathia@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बघाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हुई हवा, फिर से ग्रेप-3 लागू; देखें किन चीजों पर रहेगी पाबंदियां

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेप-3 (GRAP 3) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस कारण कई चीजों पर रोक लग जाएगी। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा जिससे हाईवे पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया। आगे विस्तार से जानिए किन-किन चीजों पर पाबंदियां रहेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुधवार को ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पूरे एनसीआर में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू होने से कई चीजों पर रोक लग जाएगी।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़ने पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उधर, आज सुबह के समय कोहरा भी घना छाया रहा, जिस वजह से लोगों को हाईवे पर वाहन चलाने में काफी परेशानी हुई।

बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 इंजन वाले 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर लगी रोक
एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के अनुसार, प्रदूषण का स्तर अभी घटने की संभावना नहीं है। इसी के

मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेप तीन लागू कर नौ सूत्री प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।

इसके तहत एनसीआर में विध्वंस और ऐसे सभी निर्माण कार्य पर सीएक्यूएम ने प्रतिबंध लगा दिया है जिनसे धूल उड़ने पर प्रदूषण फैलता है। यानी अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और विध्वंस कार्य बंद रहेंगे। अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट रहेगी।

दिव्यांग लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी
इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन वाले चार पहिया वाहनों (कार) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन दिव्यांग लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसलिए दिव्यांग अपने व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन की कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएस चार डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।

सीएक्यूएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 13 दिवंबर को ग्रेप तीन में शामिल नए प्रविधानों का भी पालन करना होगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में पांचवीं कक्षा तक स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा। अभिभावक व बच्चे आनलाइन या आफ लाइन



पढ़ाई का विकल्प चयन कर सकते हैं। दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन पम्पजीवी (मोडियम गूड्स व्हीकल) का राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी गई है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन के हल्के व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के ड्यूटी के समय में बदलाव कर

प्रदूषण के मद्देनजर बरतें ये सावधानी

- अधिक देर तक बाहर न रहें
- बाहरी गतिविधियों के समय अधिक ब्रेक लें और भारी एक्टिविटी से बचें
- अस्थमा के मरीज दवा पहुंच जें रखें
- यदि कफ, सांस फूलने जैसी समस्या आती है तो दवा लें
- दिल के मरीज को यदि सांस फूलने व बेहोशी जैसी समस्या आ रही है तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं
- स्वस्थ लोगों को अगर अचानक बेहोशी जैसी समस्या आती है तो अलर्ट रहें
- घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं

बड़ी खुशखबरी: नमो भारत ट्रेन से यात्रा हुई सस्ती; अब इतने रुपये की होगी बचत

नमो भारत ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब एनसीआरटीसी (NCRTC) ने एनसीएमसी कार्ड इस्तेमाल करने पर हर यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट देने का एलान किया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को वित्तीय लाभ प्रदान करना और पेपरलेस टिकटिंग को बढ़ावा देना है। यात्री नमो भारत मोबाइल ऐप के जरिए खरीदे गए टिकटों पर भी छूट का लाभ उठा सकते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज
गाजियाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी, NCRTC) ने नमो भारत ट्रेन से यात्रा करने वालों को थोड़ी राहत दी है। अब एनसीएमसी कार्ड इस्तेमाल करने पर हर यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि, यात्रियों को इससे बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी।

एनसीआरटीसी की यह पहल हाल ही में लॉन्च किए गए लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम का विस्तार है, जिसके अंतर्गत 'नमो भारत' मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे गए टिकटों पर छूट प्रदान की जा रही है। इस पहल के साथ, यात्री अब नमो भारत ट्रेनों में अपनी प्रत्येक यात्रा पर एनसीएमसी कार्ड से भी छूट का आनंद ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत वे जितनी अधिक यात्रा करेंगे, उतनी ही अधिक बचत कर सकेंगे।

सस्ता हुआ नमो भारत का सफर

एकत्रित पॉइंट्स एनसीएमसी खाते में किए जाएंगे जमा

लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत, यात्री एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करके नमो भारत ट्रेनों में यात्रा पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर एक पॉइंट अर्जित करेंगे। प्रत्येक लॉयल्टी पॉइंट का मूल्य 0.10 (10 पैसे) है, और एकत्रित पॉइंट्स यात्री के एनसीएमसी खाते में जमा किए जाएंगे।

100 रुपये की यात्रा पर 10 रुपये की छूट बता दें कि अगर कोई यात्री 100 रुपये यात्रा पर खर्च करता है तो उसके एनसीएमसी खाते में 100 अंक (10 के बराबर) जमा किए जाएंगे। यह ऑफर किसी भी एनसीएमसी कार्ड पर उपलब्ध है। स्टेशन के टिकट काउंटर पर इन पॉइंट्स को रिडीम करके छूट का लाभ उठाया जा सकता है। एनसीआरटीसी की पहल से लाखों लोगों को होगा फायदा

एनसीआरटीसी ने हाल ही में लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत यात्रियों को 'नमो भारत' (Namo Bharat) एप के जरिए खरीदे गए टिकटों पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। एप के जरिए डिजिटल क्यूआर टिकट खरीदने और एनसीएमसी कार्ड के इस्तेमाल पर छूट देने की इस पहल का उद्देश्य न केवल यात्रियों को होगा फायदा

एनसीआरटीसी ने हाल ही में लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत यात्रियों को 'नमो भारत' (Namo Bharat) एप के जरिए खरीदे गए टिकटों पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। एप के जरिए डिजिटल क्यूआर टिकट खरीदने और एनसीएमसी कार्ड के इस्तेमाल पर छूट देने की इस पहल का उद्देश्य न केवल यात्रियों को होगा फायदा

नमो भारत ट्रेन रुट

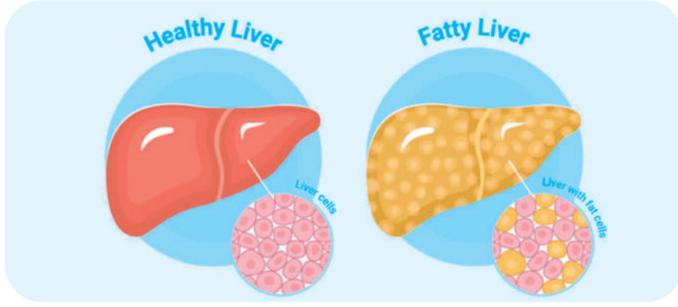
आनंद विहार ससयें काले खां जगपुरा

मोदीपुरम डिपो
देगमुल
शताब्दी नगर
मेरठ साउथ
मोदीनगर नार्थ
मोदीनगर साउथ
दुहाई डिपो
मुल्तार
साहिबाबाद
न्यू अशोक नगर
जगपुरा

संश्लेषित रुट
निष्पन्न रुट
मेरठ-आरआरटीसी कोठी
रौतम
मेरठ-आरआरटीसी रोडम

यात्री, प्रत्येक यात्रा के साथ एकत्रित लॉयल्टी बोनस को अनलॉक कर उसे किफायती बना सकते हैं।
ऐसे भी मिलेगा एप का फायदा
यात्रियों के अधिक कुशल और आरामदायक यात्रा अनुभव के लिए उन्हें नमो भारत मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एप के हर नए उपयोगकर्ता को एप डाउनलोड करने पर 50 रुपये (500 लॉयल्टी पॉइंट्स के बराबर) मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता दूसरों को एप रेफर करके अतिरिक्त 500 लॉयल्टी पॉइंट्स भी कमा सकते हैं।
गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है एप
बता दें कि रेफर करने वाले और रेफरी दोनों को 50 रुपये (500 लॉयल्टी पॉइंट्स के बराबर) मिलेंगे, जो उनके संबंधित खातों में जमा किए जाएंगे। अर्जित किए गए सभी लॉयल्टी पॉइंट्स क्रेडिट की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध हैं, जो नियमित, सतत यात्रा और एप के साथ निरंतर जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। नमो भारत एप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
ये यात्री-केंद्रित पहल नमो भारत यात्रियों के लिए किफायती, सुविधाजनक और समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की एनसीआरटीसी की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ये आधुनिक, जिम्मेदार और कुशल परिवहन को बढ़ावा देने वाले अभिनव समाधानों को लागू करने के प्रति एनसीआरटीसी के समर्पण को भी दर्शाते हैं।

फैटी लीवर



आज हम फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे। फैटी लीवर एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धीरे-धीरे लीवर में वसा जमा होने लगती है। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्हें फैटी लीवर है तो अपच या गैस्ट्रिक से जुड़ी पेट की सारी शिकायतें इसी बीमारी के कारण होती हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। फैटी लीवर का एक मुख्य कारण शराब का सेवन है, इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जिनके सेवन से लीवर में फैट जमा हो सकता है इसके अलावा, हेपेटाइटिस बी, सी जैसे वायरल संक्रमण से लीवर में समस्या हो सकती है जिससे लीवर में वसा का निर्माण भी हो सकता है। आज के दौर में एक नया कारण सामने आया है जो हमारी जीवनशैली से जुड़ा है। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ जैसे उच्च रक्तचाप, शुगर, मोटापा और रक्त में उच्च कोलेस्ट्रॉल भी इसके कुछ कारण हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे लीवर में प्रवेश करता है और फैटी लीवर का कारण बनता है। इस बीमारी को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। संक्षेप में हम इसे NAFLD कहते हैं। एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग वह बीमारी है जो शराब के सेवन से होती है। दोनों के कारण अलग-अलग हैं लेकिन बीमारी का असर लगभग एक जैसा है।

क्या यह फैटी लीवर मानव शरीर के लिए हानिकारक है? ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में फैटी लीवर से मरीजों को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में, लगभग 15-20% लोगों में, जिनमें फैटी लीवर होता है, लीवर कोशिकाओं में मौजूद वसा कोशिकाओं में सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है। हम इसे NASH चरण कहते हैं यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। एनएएसएच के कुछ प्रतिशत रोगियों में यह बीमारी और भी बढ़ सकती है। प्लेन स्टीटोसिस या साधारण स्टीटोसिस में जहां यकृत कोशिकाओं में कोई सूजन नहीं होती है, यह वर्षों तक बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है लेकिन NASH स्टेज में जहां कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, धीरे-धीरे लीवर खराब हो सकता है। धीरे-धीरे जब लीवर में सूजन आ जाती है, निम्नानुक्रम पड़ जाते हैं तो इसे हम स्फ़ारिंग कहते हैं। 15 से 20 साल में पूरा लीवर खराब हो जाता है और

कभी-कभी खराब भी हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसी स्टेज भी आती है जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बहुत ही दुर्लभ स्थिति है और केवल 8% लोग ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बीमारी बहुत आम है इसलिए अगर हम आम जनता की बात करें तो लगभग 30% लोगों को यह एनएएसएच बीमारी हो सकती है जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है और जिन लोगों को मोटापा, रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह की समस्या है, ऐसी 60% आबादी को फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो शुरूआती चरण में इसके कोई भी लक्षण नजर नहीं आते हैं। लेकिन लगभग 10-15% लोगों में ऐसा देखा जाता है कि हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में खिंचाव या भारीपन महसूस होता है जो इस बीमारी के कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई अन्य लक्षण नहीं है, ये बीमारी के बहुत अंतिम चरण में देखे जा सकते हैं। इसलिए इस बीमारी का शुरूआती चरण में ही निदान करना जरूरी है ताकि इसका इलाज किया जा सके।

आजकल अल्ट्रा साउंड जैसे बाँड़ी चेकअप के जरिए फैटी लीवर का पता लगाया जा सकता है। या फिर अगर आप किडनी के लिए पेट का अल्ट्रा साउंड करा रहे हैं तो उसमें भी फैटी लीवर का निदान हो सकता है।

क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, इसका इलाज अवश्य संभव है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक जीवनशैली से संबंधित बीमारी है, इसलिए जो बीमारियाँ इसका कारण बन रही हैं यदि हम उन्हें ठीक से नियंत्रित करते हैं जैसे कि यदि हम मोटापा, बीपी, शर्करा स्तर को नियंत्रित करते हैं तो सामान्य है और यदि हम रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, तो हम इस बीमारी को रोक सकते हैं और जिन लोगों को यह बीमारी एडवेंस स्टेज में है उन्हें ठीक किया जा सकता है।

ऐसा देखा गया है कि अगर हम अपना वजन 5 से 10% तक कम कर लें तो इस बीमारी पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब है कि हमें रोजाना 30 मिनट तेज चलना चाहिए, हमें अपने खान-पान की आदतों में बदलाव करना चाहिए और हमें कम तला-भुना और मीठा खाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो हमें इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए अपनी कैलौरी में 30% की कटौती करनी चाहिए।

अंत में मैं है ये बताना चाहेंगे चूंकि यह जीवनशैली से संबंधित बीमारी है, अगर हम अन्य सभी बीमारियों पर नियंत्रण रखें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं तो हम इसे रोक सकते हैं और आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से भी हम लीवर को सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं।



महात्मा गांधी की पुण्यतिथि

30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिनकी हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे ने इसी दिन की थी। महात्मा गांधी, जिन्हें भारत में प्यार से रबापू कहा जाता है, ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से अहिंसा या अहिंसा की शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने मूल्यों और सिद्धांतों से दुनिया भर के नेताओं को प्रेरित किया।

दिन 30 जनवरी को मुख्य रूप से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। लेकिन यह दिन शहीद दिवस या शहीद का नेतृत्व किया और उनमें योगदान दिया,

करने और उन्हें सम्मान देने का दिन है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।

इतिहास 30 जनवरी, 1948 को जब महात्मा गांधी अपनी पोलियों के साथ दिल्ली के बिडला भवन में शाम की प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तो हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में तीन गोलीयां दाग दीं। रिकॉर्ड के अनुसार, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। हर साल महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जाता है क्योंकि देश के लोग महात्मा गांधी पुण्यतिथि मनाते हैं।

महत्व महात्मा गांधी को पूरे देश में शांति और अहिंसा का अभ्यास करने के लिए लोगों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत में कई स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया और उनमें योगदान दिया,

जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह शामिल हैं। 1930 में, उन्होंने नमक सत्याग्रह भी शुरू किया और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक एक मार्च निकाला।

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे देश में प्रार्थनाएँ की जाती हैं। सरकारी अधिकारी, नेता और नागरिक देश के लिए अपने प्राणों को अर्पित देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों और प्रतिमाओं पर इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

शहीद दिवस के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान में शहीदों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने और उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौन रखना भी शामिल है।

अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव, कैरियर, रोग और उपाय



ज्योतिषाचार्य पं योगेश पौराणिक



अश्विनी नक्षत्र गुण, दोष और उपाय

अश्वनी नक्षत्र, आकाश में तारामंडल का आरंभिक बिंदु होने से यह सभी कार्यों के आरंभ को दर्शाता है।

अश्वनी का शाब्दिक अर्थ अश्वी अर्थात् घोड़े की पत्नी घोड़ी से है। अश्वनी का प्रतीक चिह्न घोड़े का सिर है जो कि आरंभ को दर्शाता है तथा नक्षत्रपति केतु ग्रह को माना गया है। सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार इस नक्षत्र के स्वामी देवता है जो कि सत्यनिष्ठ, वैधक और शास्त्र के ज्ञाता है। इसके अलावा अश्वनी नक्षत्र का संबंध विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी से भी है क्योंकि सभी कार्यों का आरंभ इन्हीं की पूजा से होता है।

स्वभाव : अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातक के स्वभाव में प्रायः तेजी, फुर्ती, शीघ्रता स्पष्ट देखने को मिलती है। यह जिंदादिल, खुशमिजाज, स्पष्टवादी तथा बिना समय

नष्ट किए काम करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी बात को शीघ्र समझ कर, सही निर्णय लेने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। वे दिखने में गठीले, आकर्षक, पुष्ट देह के स्वामी होते हैं। बहुत समय तक युवा बने रहने की अद्भुत क्षमता अश्वनी नक्षत्र की विशेषता है।

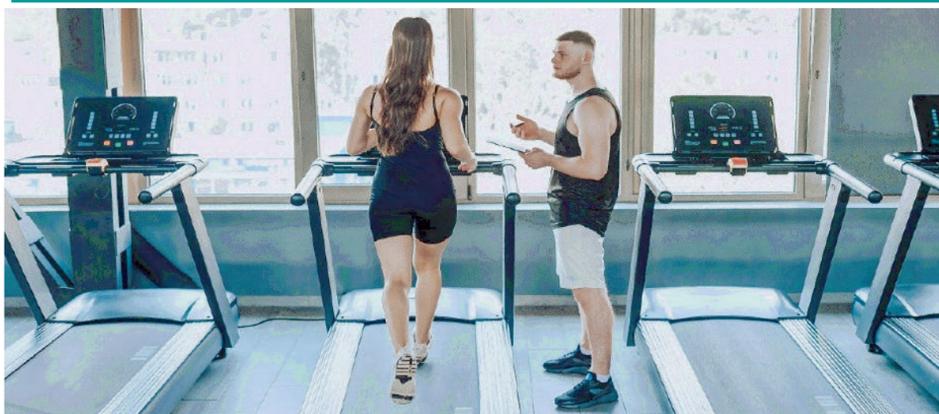
श्री वाराहमिहिर के अनुसार अश्वनी नक्षत्र के जातक बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, सजने संवरने के बहुत शौकीन होते हैं। कैरियर : अश्वनी नक्षत्र में जन्मे

जातक अक्सर साहस और शौर्य तथा जोखिम भरे कार्यों में सफल देखे गए हैं। वैज्ञानिक, खिलाड़ी, सेना नायक, पुलिस विभाग, यांत्रिक अभियंता, फार्मिस्ट, रिपेरिंग का काम, स्वर्ण आभूषण निर्माता, कार रेस, नृत्य एवं परिवहन उद्योगों में सफलता प्राप्त करते हैं।

रोग: सभी प्रकार के वात रोग तथा शरीर में अत्यधिक चोट लगने से अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातक प्रभावित होते हैं। उपाय : अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातक

जब कभी जीवन में कष्टों का अनुभव करें तब उन्हें भगवान गणेश के मंत्र ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। इसके अलावा जब भी अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो उस दिन एक माला ॐ ऐं वीज मंत्र जप करने से जीवन के सभी कार्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान गणेश तथा हनुमान जी की आराधना अश्वनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए विशेष सिद्धिदायक होती है।

60 दिनों में 10 किलो वजन कम करें, फिटनेस कोच के कार्डियो हैक पर विशेषज्ञ ने अपनी राय साझा की



फिटनेस कोच दीक्षा मलिक ने लोगों को ट्रेडमिल पर झुकाव के साथ चलने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि वजन घटाने के लिए 7 के झुकाव और 3.5 की गति पर पांच मिनट तक चलें। फिर 9 के झुकाव और 3.8 की गति पर स्विच करें और पांच मिनट तक चलें।

क्या आप जानते हैं कि आप बिना दौड़े 10 किलो वजन घटा सकते हैं, वो भी सिर्फ 60 दिनों में कैसे? फिटनेस कोच दीक्षा मलिक ने हाल ही में एक हैक शेयर किया है। इस हैक को आजमाकर लोग ट्रेडमिल पर चलकर सिर्फ 60 दिनों में 10 किलो वजन घटा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?

फिटनेस कोच दीक्षा मलिक ने लोगों को ट्रेडमिल पर झुकाव के साथ चलने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि वजन घटाने के लिए 7 के झुकाव और 3.5 की गति पर पांच मिनट तक चलें। फिर 9

के झुकाव और 3.8 की गति पर स्विच करें और पांच मिनट तक चलें। फिर 11 के झुकाव और 4 की गति पर स्विच करें और पांच मिनट तक चलें। फिर 3.8 की गति पर पांच मिनट के लिए झुकाव को 9 पर लाएं। फिर 12 के झुकाव और 4 की गति पर स्विच करें और पांच मिनट तक चलें। इस कार्डियो हैक के 25 मिनट से आप 19 किलो वजन कम कर सकते हैं।

दीक्षा मलिक का हैक कितना कारगर?
इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में, स्पर्श अस्पताल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सतीश एल. ने फिटनेस कोच के इस हैक को प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में वसा घटाने के लिए प्रभावी हो सकता है। यह कैलौरी बर्न करने में मदद करता है और दौड़ने जैसी उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों की तुलना में जोड़ें पर कम असर डालता है।

डॉ. सतीश ने कहा, 'झुकाव पर चलने से ग्लूटस, हैमस्ट्रिंग और पिंडलियों सहित प्रमुख मांसपेशी समूह सक्रिय होते हैं, जो दुबली

मांसपेशियों के निर्माण और चयापचय को बढ़ावा देने में सहायता कर सकते हैं। कई लोग इसे धीरे-धीरे वजन घटाने के लिए उपयोगी पाते हैं, लगातार प्रयास और संतुलित आहार के साथ कई हफ्तों में 10 किलो या उससे अधिक वजन घटाने का लक्ष्य रखते हैं।'

हालांकि, डॉक्टर ने लोगों को इस हैक को आजमाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर यह आसन ठीक से नहीं किया जाए तो इससे पीठ के निचले हिस्से, घुटनों और टखनों पर दबाव पड़ता है। इसलिए सावधान रहें।

डॉ. सतीश ने कहा, 'शुरुआती लोगों को हल्के ढलान से शुरुआत करनी चाहिए, धीरे-धीरे ताकत और सहनशक्ति बढ़ने के साथ इसे बढ़ाना चाहिए। सही फॉर्म सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनर से सलाह लेना जरूरी है, साथ ही स्पोर्टिव फुटवियर पहनना भी जरूरी है। हमेशा अपने शरीर की सुनें और बहुत ज्यादा जोर लगाने से बचें, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल से चोट लगने से लंबे समय तक जोड़ों की समस्या हो सकती है।'

प्रयागराज महाकुंभ हादसा



महाकुंभ में हादसा

प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ।

नरेंद्र मोदी
वीवीआईपी ने अंत में 14 की जान ले ही ली प्रयागराज के महाकुंभ में:

आज प्रयागराज का एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें श्रद्धालुगण की भीड़ कद कारण एक VIP गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि उन्हें रोक दिया गया था उनका आक्रोश स्वाभाविक था। केवल उत्तर प्रदेश में 80 सांसद, 403 विधायक, 100 विधान परिषद सदस्य, 31 राज्यसभा सांसद हैं। हर जिला और मंत्रालय व सचिवालय के IAS को गिन लें तो हजारों का संख्या पार कर जाए, फिर प्रयागराज में CRPF, वायुसेना, आर्मी सबका बेस है उनके बड़े अधिकारी...फिर पूरे देश के सांसद, केंद्र के मंत्री,

केंद्र के अधिकारी, दूसरे राज्य के बड़े नेता व अधिकारी, फिल्मी दुनिया के हस्ती, उद्योगपति...इन सबमें से रोजाना कोई न कोई पहुंच रहा है और उनके आगमन पर VIP मूवमेंट के नाम पर बाकी श्रद्धालु व नगरवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इनके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। महाकुंभ का नंबर 1 व्यवस्था के बीच केवल VIP मूवमेंट ही एक खामी है।

सब कुछ सामान्य था या कथित वीवीआईपी जिम्मेदार है इस घटना के लिए !

एलजी के भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अगर सक्षम नहीं हैं तो पद छोड़ दें*

सुष्मा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के पानी के मुद्दे पर भाजपा शासित हरियाणा सरकार का बचाव कर रहे एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने लोगों के जीवन से जुड़े पानी के मामले पर राजनीति करने पर एलजी की कड़ी निंदा की है। सीएम ने मांग की है कि एलजी साहब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं या फिर अपना पद छोड़ दें। सीएम आतिशी ने कहा कि एलजी साहब के पत्र में भी स्वीकार किया गया है कि पानी में अमोनिया का स्तर तय सीमा से 700 फीसद ज्यादा है, फिर भी उन्होंने जनहित की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पानी की गुणवत्ता का मुद्दा बार-बार आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायकों ने उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में तब दखल दिया, जब दिल्ली के लोगों के लिए साफ पानी देने के हमारी मांग को नजरअंदाज किया गया। अगर एलजी साहब को सच में दिल्ली की जनता की फिक्र होती, तो वह हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते और इस संकट को रोकते, लेकिन उन्होंने सच बोलने के लिए हमें निशाना बनाया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को लिखे पत्र में कहा है कि यह पत्र 28 जनवरी को आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र के जवाब में है। यह बहुत निराशाजनक है, लेकिन

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने दिल्ली के पानी में खतरनाक स्तर पर अमोनिया के मुद्दे को सुलझाने के बजाय बिना किसी आधार के आरोप लगाए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रहने और ध्यान भटकाने के लिए झूठा प्रचार किया है।

सीएम ने कहा है कि यह कोई रहस्य की बात नहीं है कि आपने हमेशा राजनीतिक मामलों में अपनी रुचियां बनाए रखी हैं, लेकिन इस गंभीर मामले में, जो जनता की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है, मैंने उम्मीद की थी कि आप राजनीति को एक तरफ रखेंगे। लेकिन आपने अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादारी निभाई, भले ही इससे दिल्लीवासियों की जान और सेहत पर असर पड़ा। अगर आपने अरविंद केजरीवाल पर हमले करने के बजाय पानी में अमोनिया के उच्च स्तर के खतरों की जांच करने में अपनी ऊर्जा लगाई होती, तो आपको पता होता कि इस तरह का प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है। पानी में अमोनिया का उच्च स्तर शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है और विकास संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। खासकर बच्चों और उन लोगों के लिए जिनकी पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हैं।

सीएम आतिशी ने कहा है कि आपने अरविंद केजरीवाल के बयान को आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य कहा है। लेकिन जो वास्तव में आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है, वह है इस पानी संकट के प्रति आपकी उपेक्षा। दिल्ली



जल बोर्ड का नियंत्रण आपके पास होते हुए भी आपने इस समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और न ही जनता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए कोई गंभीर प्रयास दिखाए। जो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, वह यह है कि आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उन लोगों के हितों से अधिक प्राथमिकता दी, जिनकी सेवा का वादा आपने किया था।

सीएम आतिशी ने आगे कहा है कि आपको

ध्यान नहीं दिया गया। यह कोई राजनीतिक चाल नहीं है, यह दिल्लीवासियों के पीने के साफ पानी मुहैया कराने मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई, जिसे आपकी सरकार ने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के कारण छोड़ दिया है।

सीएम आतिशी ने कहा है कि आपने हम पर उतेजक बयान देने का आरोप लगाया है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या यह उतेजक नहीं है कि जानबूझकर जहरीला पानी दिल्लीवालों के घरों में दिया जाए? क्या यह जिम्मेदारी से नहीं भागना है कि लाखों लोगों की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए भाजपा-शासित हरियाणा सरकार का बचाव किया जाए? आपकी प्राथमिकताएं साफ हैं, आप दिल्ली के लोगों की जान की सुरक्षा के बजाय भाजपा की छवि को बचाने को अधिक महत्व देते हैं। आपके पत्र में संकट की गंभीरता को हलका दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जो सचवाई को छिपाने का काम करती है। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि सभी को प्रशासनिक बहानों के नीचे दबाया नहीं जा सकता। यमुना में अमोनिया का स्तर समान्य से 700 फीसद से ज्यादा है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे आप नकार नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी रिपोर्ट्स क्यों न बदलें। जो आप गलत का बचाव कर रहे हैं, आप दरअसल उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, जिनकी सेवा के लिए आप जिम्मेदार हैं।

सीएम आतिशी ने कहा है कि आपकी हरियाणा सरकार का लगातार बचाव और दिल्ली के पानी की आपूर्ति में प्रदूषण के खिलाफ आपकी निष्क्रियता एक अहम सवाल उठाती है कि आपकी निष्ठा कहाँ है? दिल्ली के लोगों के साथ या हरियाणा में आपकी पार्टी की सरकार के साथ है? अगर आपको वाकई दिल्ली के निवासियों की फिक्र होती, तो आप तुरंत कदम उठाते। आप हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते और इस संकट को रोकने की कोशिश करते। इसके बजाय, आपने सच बोलने वालों पर हमला करना शुरू कर दिया।

सीएम ने कहा है कि यह संकट राजनीति के बारे में नहीं है; यह लाखों लोगों की जानों के बारे में है। यह एक ऐसा मौका है, जब आप प्रशासनिक भूमिका निभा सकते हैं या दिल्ली के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे, जिनके हाथ खून से रंगे होंगे। अखिरी बार जब दिल्ली पर इतना कहर टूटा था, वह 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय हुआ था, जब उसने दिल्ली में एक भयंकर नरसंहार किया था और दिल्ली को तबाह कर दिया था। अब समय आ गया है कि आप अपनी पार्टी के एजेंडे से ऊपर उठकर पानी के संकट को हल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। अखिरी बार, आपको अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा और संविधान के अनुसार रास्ता अपनाना चाहिए।

'सुनिश्चित करें कि कोई भी पार्टी चुनाव में...' , वोटिंग से पहले दिल्ली हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अपमानजनक सामग्री का उपयोग न करें। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की पीठ ने जनहित याचिका पर यह निर्देश पारित किया। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा प्रसारित किए जा रहे ऐसे संदेशों और विज्ञापन सामग्री की जांच करने के लिए पूरी तरह से सशक्त और कर्तव्यबद्ध हैं।

उचित कार्रवाई की जाएगी

मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर, ईसीआई या कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी, जो कानून के तहत जरूरी होगी।

माहिल खराब न होने दिया जाए

विधान सभा चुनावों पर, पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई का प्रारंभिक कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। इसलिए यह ईसीआई का कर्तव्य है कि वह ऐसे संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए, जिससे माहौल खराब होने की संभावना न हो।

चुनाव स्थगित करने के अनुरोध पर, अदालत ने कहा कि चुनावों के बीच में ऐसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनहित याचिका में ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होगी

ईसीआई की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने दलील दी कि आयोग ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत का संज्ञान लिया और मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली को आरोपों की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ईसीआई ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें वायस काल सहित राजनीतिक विज्ञापनों को प्रमाणित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जब भी मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होगी, उचित कार्रवाई की जाएगी।

जनहित याचिका तीन अधिवक्ताओं की ओर से दायर की गई थी, जिसमें निंदनीय और दर्शनवाणपूर्ण सामग्री के प्रसारकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

कलकत्ता की मशहूर बिरयानी का स्वाद अब दिल्ली में - अरसलान

मुगलई पाक-कला की उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में जाना जानेवाला अरसलान, हाल ही में राजौरी गार्डन में अपने नए आउटलेट के साथ दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। लाजवाब मुगलई व्यंजन बनाने में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध, अरसलान भोजन प्रेमियों के लिए एक मात्र स्थान है जहाँ कलकत्ता का स्वाद अब दिल्ली वालों को मिल सकेगा।

मुगलई विरासत को अरसलान ने जन जन तक

पहुंचाया 6 अक्टूबर, 2002 को अपनी स्थापना के बाद से, अरसलान को मुगलई व्यंजनों की कला के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के

लिए जाना जाता है। कोलकाता में बारह संपन्न आउटलेट और दबई में एक सफल अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के साथ, दिल्ली में उद्घाटन इसकी शानदार यात्रा में एक नया अध्याय है। अरसलान का मेनू मुगलई व्यंजनों की भव्यता के लिए एक पाक श्रद्धांजलि है, जो उन व्यंजनों को एक साथ लाता है जो कभी सम्राटों के लिए आरक्षित थे। अरसलान की प्रतिष्ठित चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी को आनंद लें, जिनमें सुगंधित

मसाले डाले गए हैं और जिन्हें पूरी तरह से धीमी आंच पर पकाया गया है। मेनू में शाही कबाब और रसीली करी की एक श्रृंखला भी है, जो मुगल साम्राज्य के स्वाद को दर्शाती है। हर व्यंजन पाक परंपराओं के

रहकर काम किया है। वह भाजपा युवा

मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मीडिया प्रभारी, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, भाजपा जिला क्रोल बाग के कोषाध्यक्ष व उपाध्यक्ष और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहे हैं।

संजीव अरोड़ा करीब 30 साल सामाजिक क्षेत्र में जनसेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। अपनी संस्था 'इंद्रप्रस्थ संजीवनी' के तहत करीब 50 हजार लोगों की टीम के साथ पूरी दिल्ली में समाज सेवा का काम कर रहे हैं। संजीव अरोड़ा केपीएस गिल फाउंडेशन और नारायण विहार, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा यह अनेकों महामंडलेश्वर संतों के आशीर्वाद से गंगा पुत्र की उपाधि से सम्मानित हैं। हैं इनका आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूँ।

वहीं, "आप" विधायक दुर्गाश पाठक ने कहा कि संजीव सिंह और विधायक दुर्गाश पाठक ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजीव अरोड़ा अपनी पूरी टीम के साथ भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। संजीव अरोड़ा पिछले 25 वर्षों से भाजपा से जुड़े रहे हैं और इस दौरान उन्होंने वहाँ अलग-अलग पदों पर

प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है, जिसे मसालों, ताजी सामग्री और सदियों पुरानी तकनीकों के गुप्त मिश्रण से तैयार किया जाता है।

अरसलान के सीईओ रागिव परवेज़ कहते हैं, रहम दिल्ली के खाने के शौकीनों के लिए अरसलान को लाने के लिए

रोमांचित हैं। दिल्ली में प्रामाणिक, शाही स्वादों की गहरी सराहना है, और हम राजधानी के साथ मुगलई विरासत का स्वाद साझा करने के लिए उत्साहित हैं। हमारी खास बिरयानी से लेकर शाही कबाब और स्वादिष्ट करी तक, हर व्यंजन मुगलई राजसभों को समर्पित है - जिसे प्यार, परंपरा और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ तैयार किया गया है।"

दिल्ली में अरसलान का अनुभव मुगलई व्यंजनों की भव्यता को दर्शाने के लिए

आदमी पार्टी परिवार में इनका स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके आने से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की इस मुहिम को और ताकत मिलेगी।

इस दौरान संजीव अरोड़ा ने कहा कि मैं पिछले 25 सालों से भाजपा से जुड़ा हूँ, लेकिन आज उसकी वह विचारधारा नहीं रही जो 25 साल पहले थी। इतने वर्षों से पार्टी की सेवा करने के बाद जिस आधार पर टिकट बांटे गए, जिसमें न सिर्फ मुझे, बल्कि मुझसे भी कई वरिष्ठ लोगों को एक तरफ करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो अभी हाल ही में पार्टी से जुड़ा। उस उम्मीदवार के बारे में सभी जानते हैं कि वह रात 8 बजे से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलता नहीं है। किसी का फोन नहीं उठाता है। ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने पता नहीं क्या सोचकर टिकट दिया है इससे राजेंद्र नगर का हर कार्यकर्ता आहत है। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर पंक्ति में खड़े अखिरी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। वह दिल्ली के



झुग्गीवालों के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए भी योजनाएं बना रहे हैं। कुछ दिन पहले तक भाजपा चाहती थी कि केजरीवाल रेवडी बांट रहे हैं, लेकिन आज भाजपा क्या कर रही है? हमने पुजारियों के लिए प्रकोष्ठ बनाया और उनके लिए कई काम करने की बात कही



'पहले यमुना जी का पानी पीकर दिखाओ, फिर मैं अस्पताल में मिलूंगा', राहुल गांधी ने केजरीवाल को दिया खुला चैलेंज

राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल पर हमला राहुल गांधी ने आज बवाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को यमुना का पानी पीने की चुनौती दी है। राहुल ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों ही आरक्षण के खिलाफ हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली चुनाव प्रचार के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बवाना में जनसभा करने पहुंचे। राहुल गांधी के निशाने पर भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल थे। राहुल ने दोनों पर हमला करते हुए कहा कि पानी की समस्या है यहाँ। पाने का पानी नहीं मिलता है। गंदा पानी मिलता है। महंगा पानी खरीदना पड़ता है। मोदी जी ने आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया है।

जहाँ भी जाते हैं धर्म को धर्म से जाति को जाति से लड़ाते हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। आपका धन अंबानी-अडानी जैसे अबपतियों को पकड़ा देते हैं। मोदी सरकार ने बीस-पच्चीस अरबपतियों का सोलह लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ किया। आप अपने बच्चों को निजी कॉलेज विद्यालय में भेजते हो। बीमार होते हो। प्राइवेट

अस्पताल भेजते हो। जितना आप जीएसटी देते हो उतना ही अंबानी-अडानी देते हैं।

नोटबंदी-जीएसटी के कारण छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेस बंद

राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक शर्ट खरीदो वही शर्ट अडानी खरीदेगा। उतना ही जीएसटी देगा। पहले पब्लिक स्टेकर होता है। गरीब लोगों की जगह होती थी। रोजगार मिलता था। सब बंद हो गया। निजीकरण हो गया। नोटबंदी और जीएसटी के साथ छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेस को बंद कर दिया।

भारत के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। मोदी और केजरीवाल सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता है। लाखों रुपये खर्च करके कॉलेज की डिग्री लेते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर का सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले युवा ने बताया कि लाखों रुपये देकर सिविल इंजीनियर की डिग्री ली है और कुली का काम करना पड़ रहा है।

दिल्ली में केजरीवाल ने सबसे बड़ा घोटाला किया-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने AAP संयोजक पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने लंबे भाषण किए। पहले छोटी गाड़ी में चूमते थे। मफले लिए घमते थे। बिजली के खंबे पर चढ़ जाते थे। कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा।



उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला। करोड़ों रुपये का घोटाला किया। उनकी पार्टी और उनके लोगों ने किया है। भ्रष्ट सरकार चलाई है। मोदी जी झूठे बयान देते हैं। हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं। वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। पांच साल पहले केजरीवाल ने कहा था कि यमुना में स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। पांच साल हो गए। आज तक केजरीवाल ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल जी शीशमहल में रहते हैं। करोड़ों रुपये के मकान में रहते हैं। साफ-सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान

करते हैं।

राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर केजरीवाल से पूछे सवाल

लोकसभा में मैंने कहा कि पंद्रह फीसदी दलित, पचास फीसदी पिछड़े, पंद्रह फीसदी अल्पसंख्यक और आठ फीसदी आदिवासी की आबादी है। जाति जनगणना कराएँ और पता लगाएँ कि कितनी आबादी है और कितनी हिस्सेदारी है। मोदी जी ने जाति जनगणना नहीं की गई। हमने कहा कि हम करके दिखाएँगे। दिल्ली में सरकार आएगी तो हम कर दिखाएँगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि केजरीवाल

(Arvind Kejriwal) से पूछना चाहता हूँ कि पचास फीसदी की आरक्षण की जो दीवार बना रखी है, मैंने कहा कि इस पचास फीसदी की दीवार को तोड़ देंगे। इससे ज्यादा बढ़ा देंगे। केजरीवाल जी आप साफ बता दें कि आप आरक्षण को पचास फीसदी से ज्यादा करना चाहते हो या नहीं। केजरीवाल और मोदी दोनों ही आरक्षण के खिलाफ हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी के खिलाफ हैं।

जब अल्पसंख्यकों पर आक्रमण होता है तो केजरीवाल जी कहाँ थे। क्या केजरीवाल जी आपके साथ खड़े हुए। आपके लिए लड़ें। बिल्कुल नहीं। केजरीवाल गरीबों, आरक्षण, दलितों के खिलाफ हैं।

मोदी जी के नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है

दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान है। हमारा मानना है कि सभी लोग समान हैं। हर धर्म और जाति का सम्मान होना चाहिए। मोदी जी के नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मोदी से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) नहीं डरते हैं। उल्टा नरेंद्र मोदी जी हमसे डरते हैं।

हम संविधान को बचाने का काम करते हैं। संविधान में साफ लिखा है कि सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए। अरबपतियों की सरकार नहीं होगी चाहिए। मोदी

जी आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम रहे हैं। मुकाबला कांग्रेस पार्टी देती है।

'आज आप जाकर यमुना का पानी पी लीजिए'

कांग्रेस पार्टी (Delhi Congress) के नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। हर हजार किलोमीटर। चले। देश को हमने बोला कि यह देश नफरत का देश नहीं है। नफरत मोदी फैलाते हैं। इस देश के दिल में नफरत नहीं है। यह मोहब्बत का देश है। भाईचारे का देश है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। जहाँ भी भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं वहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी व अन्य लोग नेता मिलेंगे जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे।

हम रोजगार विकास, प्रगति की बात करते हैं। शीला जी के समय में सड़कें बनीं, विकास हुआ, हम झूठे वायदे नहीं करते थे। केजरीवाल और मोदी दोनों ही चौबीस घंटा झूठे वायदे करते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना का पानी पियूंगा। मैं चुनौती देता हूँ केजरीवाल जी जो आपने कहा था जो वायदा किया था, कि यमुना को साफ करूंगा और पानी पियूंगा। मैं चुनौती देता हूँ कि आप आप जाकर यमुना का पानी पी लीजिए। आप दिल्ली की जनता को यमुना का गंदा पानी पिलाते हो। आपको चुनौती देता हूँ। उसके बाद अस्पताल में मिलूंगा।

नोएडा में 640 मीटर लंबे प्लाईओवर की परियोजना रद्द, अब लोगों को कैसे मिलेगी जाम के झाम से राहत?

नोएडा में अब यातायात जाम खत्म करने के लिए एफएनजी पर तीन लेन सड़क सड़क बनाने के लिए छिजारसी कट से गोलचक्कर तक आठ मीटर चौड़ाई सड़क दोनों तरफ बढ़ाई जाएगी दो मीटर चौड़ा फुटपाथ अतिरिक्त तैयार होगा। नोएडा ट्रैफिक सेल की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सड़क चौड़ाई बढ़ाने के लिए काम करेगा।

नोएडा। नेशनल हाईवे नंबर-9 की तरफ से छिजारसी के रास्ते फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद (एफएनजी) पर आने जाने वाले लोगों को यातायात जाम से निजात दिलाने के लिए अब छिजारसी के आसपास सड़क चौड़ीकरण करने की तैयारी है।

पहले एलिवेटेड प्लाईओवर बनाना का था प्लान
पहले यहां एलिवेटेड प्लाईओवर बनाने की योजना थी, लेकिन अब यह परियोजना नोएडा प्राधिकरण में रद्द हो गई है। बता दें कि छिजारसी के आसपास अतिक्रमण का मकड़जाल है, इसे हटाकर तब सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा।

इसके लिए नोएडा प्राधिकरण का नोएडा

ट्रैफिक सेल सर्वे करा रहा है, छिजारसी के आसपास कितनी और किस प्रकार से सड़क चौड़ीकरण को किया जा सके, जिससे वाहनों का आवागमन तेज हो और पैदल पथ यात्रियों को भी सड़क से फुटपाथ पर चलाया जाए।

अभी सड़क पर अतिक्रमण के चलते लगता है जाम

ऐसे में अब तक सर्वे में निकल कर सामने आया है कि नेशनल हाईवे नंबर 9 स्थित छिजारसी कट से छिजारसी गोलचक्कर तक करीब 640 मीटर सड़क के दोनों ओर करीब आठ मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे इस रास्ते तीन लेन की सड़क को विकसित किया जा सके।

साथ ही दो मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान में इस रास्ते पर डेढ़ लेन की सड़क है, जिस पर आसपास संचालित होने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान का अतिक्रमण है। इसलिए आठ मीटर सड़क चौड़ी कर करीब 11 मीटर पर तीन लेन संचालित होगी, दो मीटर का फुटपाथ बनेगा।

फुटपाथ व सड़क पर व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले अतिक्रमण न करे। इसलिए फुपाथ किनारे बोलार्ड के जरिये बैरिकेडिंग की जाएगी। इससे सिर्फ पैदल चलने वाले ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।



नोएडा प्राधिकरण देगा खर्च

इस दौरान जिन लोगों ने अपना मकान, दुकान, होटल, अस्पताल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को बढ़ाकर सड़क तक कर लिया है, उनको तोड़ा कर पीछे की ओर समेट जाएगा, क्योंकि यह जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, जिस पर लोगों ने जबरन कब्जा कर अतिक्रमण फैला रखा है। सड़क चौड़ीकरण का काम सिंचाई विभाग की ओर से किया जाएगा, जिस पर आने वाला खर्च नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा।

काम में तेजी लाने के लिए प्राधिकरण में सर्वे करने वाली कंसल्टेंट कंपनी को निर्देश जारी कर दिए हैं, जल्द सड़क की कार्ययोजना तैयार कर

संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से अनुबंध कर समय से टेंडर प्रक्रिया को पूरा कराया जा सके। जाम में फंसने वाले लोगों को आने-जाने में सहूलियत उपलब्ध कराई जा सके।

ई-रिक्शा व आटो स्टैंड पहले से किया गया चिह्नित

छिजारसी पर आटो व ई-रिक्शा के कारण लगने वाले जाम को लेकर पहले से ही स्टैंड का स्थान चिह्नित किया जा चुका है, जिसको तैयार करने की जिम्मेदारी नोएडा ट्रैफिक सेल को दी जा चुकी है। इस व्यवस्था से यातायात जाम पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा।

इंदिरापुरम में आज से तीन दिन तक चलेगा बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस की रहेगी तैनाती



गाजियाबाद के इंदिरापुरम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने बुधवार से अभियान शुरू कर दिया है। तीन दिनों तक चलने वाले इस अभियान में निर्माण स्वास्थ्य उद्यान और जोनल प्रभारी की टीम शामिल है। यह अभियान हर दिन दोपहर दो से पांच तक चलेगा। नगर निगम के अधिकारी ने कहा है कि इस अभियान के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहेगा।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम आज से अभियान की शुरुआत करने का रहा है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के निर्देश पर टीम का गठन किया गया है।

अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने मंगलवार को टीम के साथ बैठक कर जल्दी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस बल मौजूद रहेगा।

तीन दिनों तक चलेगा अभियान
अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार ने बताया कि तीन दिन चलने वाले अभियान के लिए निर्माण,

स्वास्थ्य, उद्यान और जोनल प्रभारी की टीम को शामिल किया गया है। इंदिरापुरम से अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्माण स्वास्थ्य तथा जोनल प्रभारियों से संयुक्त बैठक करते अपर नगर आयुक्त अरुण यादव। सो. नगर निगम

इंदिरापुरम से अतिक्रमण (bulldozer Action) की शिकायत प्राप्त हो रही थीं, इनका संज्ञान लेते हुए 29 से 31 जनवरी तक तीन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

इंदिरापुरम के मुख्य मार्गों से रेहड़ी-पटरी, सरकारी भूमि पर कब्जा, ग्रीन बेल्ट पार्कों से कब्जा हटाना जाएगा। हर दिन दोपहर दो से पांच तक अभियान चलेगा। क्षेत्र में खड़े बेतरतीब वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

समस्या को लेकर निगम के खिलाफ लोगों ने किया था प्रदर्शन

वहीं पर दूसरे मामले में इंदिरापुरम के न्याय खंड-एक की करीब पांच हजार की आबादी पिछले तीन महीने से सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान है। स्थानीय लोगों

डेटिंग एप पर बनी दोस्त ने मिलने के लिए रखी शेयर ट्रेडिंग की शर्त, युवक से की 12.60 लाख की साइबर टगी

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में एक युवक डेटिंग एप के जरिए साइबर टगी का शिकार हो गया। युवती ने उसे ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 12.60 लाख रुपये टग लिए। साइबर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। युवक ने लड़की की बातों में आकर उसके बताए खाते में 12.60 लाख रुपये शेयर ट्रेडिंग के लिए भेज दिए। इसके बाद युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया।

साहिबाबाद। डेटिंग एप के माध्यम से एक युवती के संपर्क में आए युवक से ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 12.60 लाख रुपये की साइबर टगी की गई। इस मामले में शिकायत पर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

कैसे ठगों के झांसे में आया युवक?

क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित गौर ग्लोबल विलेज सोसायटी में रहने वाले अलंकार जौहरी ने पुलिस को बताया कि अमोर नाम की डेटिंग एप पर उनका अकाउंट है। अगस्त 2024 में इस डेटिंग एप के माध्यम से वह एक आदमिका नाम की युवती के संपर्क में आए, उस युवती ने अपना असली नाम साक्षी गौड़ा बताया और टेलीग्राम एप पर संपर्क करने को कहा।

टेलीग्राम एप से संपर्क करने पर युवती ने अलंकार को स्प्रॉडेक्स ग्लोबल नाम की वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करने को कहा, इसमें मुनाफा होने का लालच दिया। उसने यह भी कहा कि ऐसा करने पर वह अलंकार से मिलेगी और उसके साथ समय व्यतीत करेगी।

लड़की बातों में आकर खाते में भेज



दि 12.60 लाख रुपये

अलंकार उसकी बातों में आ गए और 12.60 लाख रुपये युवती द्वारा बताया गए खाते में शेयर ट्रेडिंग के लिए भेज दिए। इसके बाद जब युवती से मिलने को कहा तो युवती ने उससे और रुपये जमा करने को कहा, रुपये जमा करने पर उसने बात करना बंद कर दिया। इसके बाद पीड़ित अलंकार को साइबर टगी का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जमीन दिलाने के नाम पर 14 लाख टगे

उधर, एक अन्य मामले में भोजपुर थाना

क्षेत्र के गांव तलहैटा व पलौता में चार बीघा जमीन दिलाने के नाम पर 14 लाख की टगी की गई है। केस दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। गांव पलौता के किसान महेश कुमार के मुताबिक, उन्हें 2018 में जमीन खरीदनी थी। इस बीच उनके संपर्क में एक व्यक्ति आया। उसने उन्हें पलौता व तलहैटा में चार बीघा जमीन दिखा कहा कि ये सस्ते दाम में मिल जाएगा।

लोकेशन अच्छी देख महेश ने जमीन खरीदने पर सहमत दे दी। उनके बीच 10 लाख प्रति बीघा के हिसाब से जमीन का सौदा हो गया। रकम मिलने के कुछ ही दिन बाद

बैनामा कराने पर सहमत बनी। झांसे में आकर महेश ने अलग-अलग किस्तों में आरोपित को 14 लाख रुपये दे दिए, पर अब तक बैनामा नहीं किया गया है। कई बार कहने पर भी आरोपित उन्हें लगातार टरका रहा है।

परेशान आकर कुछ दिन पहले रुपये मांगे तो आरोपित ने उन्हें परिवार समेत हत्या की धमकी दी। उन्होंने भोजपुर थाने में शिकायत दी, पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस कमिश्नर से गुहार पर उनके आदेश पर अब भोजपुर पुलिस ने केस दर्ज किया। एसीपी मोदीनुर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि केस दर्ज है। जल्द आरोपित की गिरफ्तारी होगी।

दिल्ली की चुनावी लड़ाई-वादों में रेवड़ियों की भरमार छाई-टैक्स पेयर्स द्वारा पेड टैक्स की मजाक उड़ाई

चुनावी रेवड़ियों को अब मतदाताओं को प्रलोभन (रिश्त) के रूप में देखा जा रहा है
रेवड़ी कल्चर से मिशन आत्मनिर्भर भारत को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गाँदिया महाराष्ट्र

गाँदिया - वैश्विक स्तर पर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अगर हम एवरज लगाएँ तो प्रतिमाह से भी कम समय में अनेक क्षेत्रों में चुनाव होते रहते हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद जिला परिषद स्थानीय निकायों पंचायत समिति चुनाव सहित अनेक ऐसे संस्थानों के चुनाव होते ही रहते हैं इसीलिए ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल शायद बजट सत्र में लाया जा सकता है। भारत में एक समय था जब मतदाता इलेक्शन को लोकतंत्र के मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में पूजनीय समझकर चुनते थे, अर्थात् आज भी ऐसा है परंतु करीब एक दशक से चुनावी मौसम को रेवड़ियों की सौगात का मौसम कहा जाने लगा है क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी विषय चाहे कोई भी हो वह चुनाव जीतने की निश्चिन्ता चाहता है, जिसके लिए वह सीधे से नहीं बल्कि पट्टे के पीछे से मतदाताओं को रेवड़ियों रूपी रिश्त का प्रलोभन देकर अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। यह मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा कि किस तरह लाडली बहन योजना में 1500 रूपय प्रतिमाह बहनों को देने वाले प्लान ने बाजी पलट कर रख दी, व भारी मतों के अंतर से चुनाव को जीता गया, अगर इस योजना के लाभार्थियों की स्कूटिंग की जाए तो मेरा मानना है कि आधे से अधिक ऐसे निकलेंगे जो इस प्लान के पात्र ही नहीं हैं परंतु इन चीजों को नजर अंदाज किया गया व अभी भी किया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025 को हो रहे हैं, व इसका रिजल्ट 8 फरवरी 2025 को आएगा, जिसमें सभी पार्टियों द्वारा भारी मात्रा में रेवड़ियों की बातें व वादे किए जा रहे हैं। अगर हर व्यक्ति को ऐसी ही रेवड़ियाँ

प्रतिमाह मिलेंगी तो वह आलसी हो जाएगा और कौशलता शिक्षा ग्रहण कर विशेषज्ञ होने के बाद भी वह काम नहीं करेगा, क्योंकि रेवड़ियों के रूप में उसे इतनी रकम मिल जाएगी तो उसका भरण पोषण पालन हो जाएगा, फिर वह काम क्यों करेगा? जिसका सीधा-सीधा असर हमारे मिशन आत्मनिर्भर पर पड़ेगा जो रेखांकित करने वाली बात है। चूंकि चुनावी रेवड़ियों को अब मतदाताओं को रिश्त के रूप में देखा जा रहा है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे रेवड़ी कल्चर से मिशन आत्मनिर्भर भारत को पूर्ण करने में भारी कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई, वादों और रेवड़ियों की भारी भरमार छाई टैक्सपेयर्स द्वारा पेड टैक्स की मजाक उड़ाई।

साथियों बात अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की करें तो, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दल के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव के पानी की पट्टी प्रचारकों को लोगों के बीच उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 15 गार्स्टियों वाला घोषणा पत्र जारी किया है। इधर कांग्रेस भी दिल्ली में खोई अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश में जुटी है दिल्ली के सियासी दंगल में यमुना के पानी की पट्टी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यमुना में बड़ा अमानिया का स्तर हरियाणा की देन है, इस मामले में गृह मंत्री ने केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने कहा कि केजरीवाल का नया आरोप है मैंने आज केजरीवाल से सार्वजनिक तौर पर सवाल पूछा है कि भाजपा सरकार ने जहर मिलाया पानी में ऐसी दिल्ली में रिपोर्ट है क्या? किस प्रकार का जहर है, वो रिपोर्ट सार्वजनिक करें, अगर हरियाणा ने पानी रोका था तो बताएं, पानी बंद करेगी तो हरियाणा में गांव के गांव डूब जाएंगे, ये तीन चीजें उनको स्पष्ट कनी चाहिए चुनाव आयोग ने दिल्ली के पूर्व

मुख्यमंत्री और आप के संयोजक द्वारा जो आरोप लगाया है, उस पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें 29 जनवरी की शाम आठ बजे तक अपने आरोप को प्रमाणित करने को पत्र भेजा है। अगर ऐसा नहीं है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी आयोग ने यह कदम शिकायत के बाद उठाया है।

साथियों बात अगर हम आम आदमी पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र की करें तो, आप द्वारा जारी 15 गार्स्टियों तथा 5 बातें-- (1) रोजगार की गार्स्टी युवाओं को कैसे रोजगार मिले इसकी प्लानिंग की जाएगी। (2) महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपये बैंक अकाउंट में मिलेंगे। (3) संजीवनी योजना- 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्री इलाज मिलेगा। (4) पानी के बिल माफ, जो बिल भेजे गए हैं वो भरने की जरूरत नहीं। (5) हर घर में 24 घंटे साफ पानी। (6) यमुना की सफाई- केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास फंड और पूरा प्लान है। (7) दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन लेवल का बनाने का वादा। (8) डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप

योजना - दलित बच्चों को विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी। (9) कॉलेज छात्रों को प्री बस की सुविधा और दिल्ली में 50 फीसदी छूट मिलेगी। (10) पुजारी और ग्रंथियों हर महीने 18-18 हजार रुपये मिलेंगे। (11) किराएदारों को भी प्री बिजली-पानी की सुविधा मिलेगी। (12) जहां भी सौर ब्लॉक है उसको 15 दिनों में साफ किया जाएगा और पुराने सीवर को साल डेढ़ साल में बदला जाएगा (13) दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे (14) ऑटो-टैक्सी-ई-रिक्शा वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये, बच्चों को प्री कौचिंग और इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। (15) आरडब्ल्यू को प्राइवेट सिविलिटी गार्ड रखने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 15 बातें-- (1) ईमानदार मानते हो तो वोट दो, वरना रहने दो (2) फिर से

मुख्यमंत्री बनाना है तो अग्निपरीक्षा में पास करो (3) समझो सभी 70 सीटों पर केजरीवाल ही लड़ रहा है (4) बीजेपी को वोट दितो वो बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे (5) बेटा मानते हो तो वोट दो, वरना बीजेपी का बटन दबा दो।

साथियों बात अगर हम भाजपा द्वारा तीन चरणों में जारी संकल्प पत्र की करें तो, संकल्प पत्र-1- (1) वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपये पेंशन। (2) महिलाओं को 3,500 रुपये की सम्मान राशि (3) विधानसभा चुनाव जीतने पर 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर। (4) विधवाओं, बेसहारा महिलाओं की पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रूपय। (5) मातृ सुरक्षा बंदना को और ताकत देने के लिए 6 पोषण किट और हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। संकल्प पत्र-2-- (1) सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को 'केजी' से 'पीजी' तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया। (2) युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15 हजार की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति (3) तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 'डॉ. बीआर अंबेडकर स्टार्टअप योजना' के तहत 1 हजार रुपये प्रति माह का स्टार्टअप (4) ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा एवं वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप (5) घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 6 महीने की पेड मेटरनिटी लीव। पोपुल स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी होगी। संकल्प पत्र-3-- (1) पार्टी के सत्ता में आने पर 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा, जिससे बिक्री, खरीद और निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। (2) गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए कई नई योजनाओं और कल्याणकारी उपाय, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' बनाएंगी और 10 लाख रुपये

का बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना कवर देगी। (3) पारदर्शी तरीके से 50,000 सरकारी पदों को भरने, स्वरोजगार के 20 लाख अवसर पैदा करने और एक भव्य महाभारत कॉरिडोर विकसित करने का वादा (4) दिल्ली में सड़कें बनाने पर 41,000 करोड़ रुपये, रेलवे लाइन बिछाने पर 15,000 करोड़ रुपये और हवाई अड्डों पर 21,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। (5) नेशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली में 4,000 रुपये तक की मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है।

साथियों बात अगर हम बात अगर हम कांग्रेस द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र की करें तो मुख्य बातें, (1) युवा उद्यम योजना: बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8500 रुपये की सहायता दी जाएगी (2) अप्रेंटिसशिप: बेरोजगार युवकों को एक साल की अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षण) देने का वादा किया गया है। (3) सस्ता सिलेंडर: 500 रूपय में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। (4) मुफ्त राशन किट: मुफ्त राशन किट प्रदान करने का वादा किया गया है। (5) 300 यूनिट तक प्री बिजली देने का वादा। (अन्य आम उपरोक्त पूरे विवरण को



वादों की भरमार किस पर ऐतबार?

अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दिल्ली की चुनावी लड़ाई-वादों में रेवड़ियों की भरमार छाई-टैक्स पेयर्स द्वारा पेड टैक्स की मजाक उड़ाई, चुनावी रेवड़ियों को अब मतदाताओं को प्रलोभन (रिश्त) के रूप में देखा जा रहा है रेवड़ी कल्चर से मिशन आत्मनिर्भर भारत को पूर्ण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

चीनी मिलों के सामने गन्ने का संकट, समय से पहले दम तोड़ सकता है पेराई सत्र



संकट में गन्ना उद्योग

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में महाराष्ट्र में करीब सौ लाख टन गन्ना अभी तक चीनी मिलों के पास नहीं पहुंच पाया है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही गन्ने की कमी का खतरा दिख रहा है क्योंकि इस बार उत्तर भारत में पहले बाढ़ और फिर पर्याप्त ठंड नहीं पड़ने के चलते मिलों तक गन्ना पहले ही आने लगे थे।

नई दिल्ली। गन्ना उद्योग दो-तरफा संकट से गुजर रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में रैड रोट (लाल सड़न) और दक्षिण के राज्यों में बेमौसम वर्षा के चलते गन्ना के उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है। उत्पादकता भी बुरी तरह प्रभावित है। इसका सीधा असर चीनी मिलों पर पड़ रहा है। नवंबर से अप्रैल तक चलने वाला पेराई सत्र मार्च के मध्य में ही दम तोड़ सकता है।

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ (एनएफसीएसएफ) के अनुसार देश में अभी सिर्फ 507 चीनी मिलें ही चालू हैं, जबकि पिछले वर्ष 524 मिलें चालू थीं। यानी 17 मिलों को अभी तक चालू होने का इंतजार है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चीनी

मिलें बंद हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

पेराई के लिए अभी से गन्ने की कमी होने लगी है। आशंका है कि कई चालू मिलों को मार्च में ही बंद देना पड़े। ऐसे में चालू सत्र में चीनी उत्पादन में 49 लाख टन की कमी आने का अनुमान है। पिछले वर्ष 319 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस बार सिर्फ 270 लाख टन का अनुमान है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र है, जहां टॉप शूट बोर और रैड रोट (लाल सड़न) बीमारी के चलते उत्पादन नीचे चला आया है।

महाराष्ट्र और यूपी का हाल
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में महाराष्ट्र में करीब सौ लाख टन गन्ना अभी तक चीनी मिलों के पास नहीं पहुंच पाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक आठ लाख टन ज्यादा गन्ने की पेराई हो चुकी है, लेकिन जल्द ही गन्ने की कमी का खतरा दिख रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर भारत में पहले बाढ़ और फिर पर्याप्त ठंड नहीं पड़ने के चलते मिलों तक गन्ना पहले ही आने लगे थे।

फिलहाल गन्ने के अभाव में कई मिलों को घंटों बंद रखना पड़ रहा है। हालांकि ऐसी

स्थिति किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि कम आपूर्ति के चलते पेराई सत्र के आखिर में गन्ने की कीमत अच्छी मिल सकती है। अधिक से अधिक गन्ना लेने के लिए मिलों के बीच प्रारंभिक वार के हालात बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की मिलों तो अभी से ही पड़ोस के राज्य उत्तराखंड एवं बिहार से अधिक मूल्य पर गन्ना मंगाना शुरू कर दिया है।

अन्य राज्यों का हाल
अन्य राज्यों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उत्पादकता दर में 20 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में गन्ने की फसल का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है। समय से पूर्व फसल फलारिंग स्ट्रेज (अर्ली-मैच्योर) में पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में सूक्रोज की मात्रा कम हो जाती है और गन्ने का वजन भी कम हो जाता है।

यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो मिलें चालू थी हैं, उन्हें गन्ने की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में भी यही स्थिति है। एनएफसीएसएफ के अनुसार तमिलनाडु में चालू सत्र के लिए 8.50 लाख टन तक ही पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले सत्र की तुलना में 10.75 लाख टन से कम है।

अमेरिकी पाबंदी का आरबीआई की मुहिम पर असर नहीं, डिजिटल करेंसी पर चलता रहेगा काम

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई ने 01 दिसंबर 2022 को देश के कुछ चयनित बैंकों के चयनित शाखाओं के जरिए सीबीडीसी को लागू किया था। तब बताया गया था कि यह निजी क्षेत्र की डिजिटल करेंसी (क्रिप्टोकॉरेसी व अन्य) की चुनौतियों को थामने का काम करेगा। लेकिन ट्रंप ने ना सिर्फ सीबीडीसी को प्रतिबंधित किया है बल्कि क्रिप्टोकॉरेसी को हरी झंडी दिखाते हुए अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की भी घोषणा की है।

नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन की तरफ से सेटल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को प्रतिबंधित करने से दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के निर्देश में डिजिटल करेंसी की व्यवस्था को लागू करने की भारत की मुहिम को धक्का लगा है। लेकिन घरेलू स्तर पर आरबीआई की तरफ से सीबीडीसी व्यवस्था को प्रसारित करने की योजना को लेकर ना तो सरकार की सोच बदली है और ना ही आरबीआई की।

आरबीआई ने 01 दिसंबर, 2022 को देश के कुछ चयनित बैंकों के चयनित शाखाओं के जरिए सीबीडीसी को लागू किया था और तब यह बताया गया था कि यह निजी क्षेत्र की डिजिटल करेंसी (क्रिप्टोकॉरेसी व अन्य) की चुनौतियों को थामने का काम करेगा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सीबीडीसी को प्रतिबंधित किया है बल्कि क्रिप्टोकॉरेसी को हरी झंडी दिखाते हुए अमेरिका को इसका सबसे बड़ा केंद्र बनाने की भी घोषणा की है।

अमेरिका की नई सरकार के उक्त फैसलों के भारत पर प्रभाव को लेकर आधिकारिक तौर



पर अभी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसका एक स्पष्ट असर सीबीडीसी को लेकर जी-20 की तैयारियों पर होने का खतरा है। नवंबर, 2020 के शिखर सम्मेलन में जी-20 देशों ने विभिन्न देशों के बीच डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता को लेकर घोषणा की थी।

तब बताया गया था कि मौजूदा भुगतान व्यवस्था के मुकाबले सीबीडीसी काफी सस्ता, पारदर्शी व सुविधाजनक होगा। बाद में जब भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 की बैठक में भी इसे एक अहम मुद्दा बनाया गया। अहमदाबाद में जी-20 के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों व आइएमएफ, विश्व बैंक जैसे दूसरे वैश्विक संस्थानों की बैठक में इस बारे में बहस हुई कि कैसे सीबीडीसी का इस्तेमाल व्यापक आर्थिक फायदे के लिए किया जाए। नई दिल्ली घोषणा-पत्र में भी इसका जिक्र किया गया।

इस दरम्यान भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, यूएई समेत 36 देशों में सीबीडीसी पर प्रायोगिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया

है। जी-20 ने वर्ष 2027 तक सीबीडीसी की एक मजबूत व्यवस्था दुनिया भर में बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति की तरफ से इससे हाथ खींचने से इस योजना पर उल्टा असर पड़ना संभव है।

सीबीडीसी को बढ़ाने पर हो रहा काम
आरबीआई की तरफ से भी सीबीडीसी को ज्यादा व्यापक बनाने का काम धीरे-धीरे चल रहा है। आरबीआई की तरफ से यह भी बताया गया था कि जून, 2024 तक भारत में 50 लाख ग्राहक सीबीडीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह संख्या एक वर्ष पहले सिर्फ 13 लाख थी। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपनी फ्लैगशिप सुभद्रा योजना को भी आरबीआई की पायलट सीबीडीसी से जोड़ने का काम किया है।

सीबीडीसी को लागू कर रहे दिल्ली स्थित मुख्यालय वाले एक बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि सीबीडीसी की रफ्तार धीमी करनी है। हालांकि यह भी तय है कि अभी इसे पूरी तरह से लांच करने को लेकर भी विमर्श नहीं चल रहा।

सनद रहे कि सीबीडीसी आरबीआई की मान्यता वाला डिजिटल करेंसी है जिसका इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को एक विशेष डिजिटल खाता (डिजिटल वॉलेट) खोलना पड़ता है और इसका खासा एप ईआर डाउनलोड करना होता है। यह भारतीय रुपये में भुगतान करने या स्वीकार करने का डिजिटल माध्यम है। आरबीआई का कहना है कि इससे सेटलमेंट करना काफी आसान है। अभी 15 भारतीय बैंकों को सीबीडीसी जारी करने की मंजूरी दी गई है।

किसानों को जल्द मिलेगी 19वीं किस्त, इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपये

नई दिल्ली। देश भर के करोड़ों किसान काफी समय से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। सरकार ने बता दिया है कि 19वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में किस दिन ट्रांसफर किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि किसानों के अकाउंट में पैसे कब आएंगे और उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा।

किसानों को कब मिलेगी 19वीं किस्त?

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जारी करेंगे। यह रकम डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर (DBT) मोड के जरिए सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। इसका लाभ देश भर के करोड़ों किसानों को मिलेगा।

e-KYC कराना है जरूरी

पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए e-KYC कराना जरूरी है। जल्द ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की अगली किस्त के पैसे अटक सकते हैं।

ओटीपी आधारित eKYC बायोमेट्रिक आधारित eKYC फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC

लाभार्थी लिस्ट में कैसे चेक करें नाम

सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट जारी करती है। इससे पता चल जाता है कि किन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें। आप नीचे दिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं:

पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट (<https://pmkisan.gov.in/>) पर जाएं।

'Beneficiary Status'

ऑप्शन सेलेक्ट करें। आधार या फिर बैंक अकाउंट नंबर नंबर भरें।

अब 'Get Data' को सेलेक्ट करें।

इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद स्क्रीन पर आपको अपनी पूरी डिटेल्स दिख जाएगी। इसके जरिये आप चेक कर सकते हैं कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की थी। इसमें लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह रकम हर चार महीने में तीन किस्तों में मिलती है। हर किस्त में 2000 रुपये डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में आते हैं।

जीएसटी के सभी पुराने बकाए को खत्म करने का मौका, ब्याज और जुर्माने से भी मिलेगी छूट

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार ने जीएसटी संबंधित सभी पुरानी डिमांड को खत्म करने का फैसला किया है। कारोबारियों को सिर्फ बकाए टैक्स का भुगतान करना होगा। इस स्कीम के तहत जीएसटी संबंधित कोई भी डिमांड अगर किसी कारोबारी को अपने पोर्टल पर दिख रहा है तो वह सिर्फ टैक्स की राशि को जमा कर जुर्माने व ब्याज दोनों से छूट पा सकता है।

नई दिल्ली। आयकर की तरह सरकार जीएसटी संबंधित विवादों को भी खत्म करने का लगातार प्रयास कर रही है ताकि कारोबारियों को राहत मिल सके। इस प्रयास के तहत हाल ही में सरकार ने जीएसटी संबंधित सभी पुरानी डिमांड को खत्म करने का फैसला किया है। कारोबारियों को सिर्फ बकाए टैक्स का भुगतान करना होगा। सभी पुराने बकाए टैक्स भरने के लिए अगले साल 31 मार्च तक का समय दिया गया है। बकाए टैक्स टैक्स का भुगतान कर देने पर उन्हें टैक्स से जुड़े ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह से छूट मिल जाएगी।

कैसे मिलेगी ब्याज और जुर्माने से छूट?



जीएसटी विशेषज्ञ और चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रवीण शर्मा ने बताया कि सरकार की इस स्कीम के तहत जीएसटी संबंधित कोई भी डिमांड अगर किसी कारोबारी को अपने पोर्टल पर दिख रहा है तो वह सिर्फ टैक्स का जमा कर जुर्माने व ब्याज दोनों से छूट पा सकता है।

मान लीजिए किसी कारोबारी पर वर्ष 2018-19 से टैक्स का बकाया है और उसने चुकता नहीं किया है तो साधारण रूप में कारोबारियों को उस बकाए टैक्स का भुगतान कर देना होगा। देर से भरने पर जुर्माना भी लगेगा। लेकिन अगले साल 31 मार्च तक बकाए टैक्स को भरने पर कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। लेकिन कारोबारी

ने उस बकाए टैक्स को अगर किसी अदालत में चुनौती दी है तो उस चुनौती को वापस लेना होगा।

गुट दिसंबर में जीएसटी का उर्सिल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी थी। इस माह इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आयकर संबंधित पुराने विवादों को समाप्त करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास स्कीम ला चुकी है। जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले साल सरकार ने जीएसटी संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को लेकर भी कारोबारियों को बड़ी राहत दी थी।

जीएसटी रिटर्न भरने में देरी पर कारोबारियों के आईटीसी फंस जाते हैं। पिछले साल सरकार ने

कारोबारियों को वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 तक के आईटीसी क्लेम के लिए एक साथ टैक्स ट्रांसफर करने का मौका दिया था।

सरकार का नरम रुख

जीएसटी विवादों से जुड़े वकील पी.सी. अग्रवाल ने बताया कि सरकार का रुख अब लगातार लचीला होता जा रहा है। अगर किसी कारोबारी पर जीएसटी का बकाया है तो सरकार से गुंजायिश करने पर उन्हें टैक्स जमा करने की माहलत आसानी से मिल जाती है। गलत रिटर्न को भी सुधार की तरफ से जीएसटी रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है। वर्ष 2017 के जुलाई में जब जीएसटी प्रणाली लागू हुई थी तो इस प्रकार की सुविधा नहीं थी।

हालांकि सरकार के बकाए पर कोई कारोबारी जबाब भी नहीं देता है, कोई संवाद नहीं करता है तो टैक्स की राशि के मुताबिक कारोबारी को सजा की भी प्रविधान है। इसके अलावा इस साल से जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी काम करने लगेगा। राज्यों की तरफ से ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति में देरी से ट्रिब्यूनल के संचालन में विलंब हो रहा है। देश भर 44 ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाना है। एक ट्रिब्यूनल में चार सदस्य होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के बूस्टर डोज का असर, शेयर बाजार में थमा गिरावट का तूफान; क्या अब ब्याज दरों में होगी कटौती?



परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई के उपायों से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। लिक्विडिटी में ढील बैंकों और NBFC को क्रेडिट ग्रोथ और रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। नोमुरा ने कहा कि आरबीआई से कदम से खासकर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक को मदद मिलेगी जिनके सामने लिक्विडिटी की समस्या थी। अब फरवरी में होने वाले आरबीआई की MPC मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। इसकी वजह आरबीआई से मिले सकारात्मक संकेत हैं। दरअसल, आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुछ उपायों का एलान किया है। इससे फरवरी में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी बढ़ गई है।

क्या ब्याज दरों में कटौती करेगा

आरबीआई?

निफ्टी 50 0.56 फीसदी बढ़कर 22,957.25 पर पहुंच गया, जबकि बीएसई सेंसेक्स 0.71 फीसदी बढ़कर 75,901.41 पर पहुंच गया। फाइनेंस सेक्टर के शेयरों 1.9 फीसदी और बैंकिंग शेयरों में 1.7 फीसदी की वृद्धि हुई। आरबीआई के लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों की बात करते, तो इसमें बॉन्ड खरीद और डॉलर/रुपया स्वैप शामिल हैं। इसके बारे में एनालिस्टों और ट्रेडर्स का कहना है कि यह फरवरी में ब्याज दरों (Repo Rate Cut) में कटौती का अहम संकेत हो सकता है।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के रिसर्च हेड नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि आरबीआई के उपायों से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। लिक्विडिटी में ढील बैंकों और NBFC को क्रेडिट ग्रोथ और रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। नोमुरा ने कहा कि आरबीआई से कदम से खासकर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक को मदद मिलेगी, जिनके सामने लिक्विडिटी की समस्या थी।

बैंकिंग शेयरों का सबसे ज्यादा

फायदा

आज एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में क्रमशः 2.5 फीसदी और 3.8 फीसदी की वृद्धि हुई। बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में क्रमशः 4.3 फीसदी और 3.7 फीसदी का उछाल आया।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी 1.3 फीसदी की तेजी आई। ब्रोकरेज फर्म सिटी का कहना है कि सिटी ने आरबीआई के फैसले से तनों को ज्यादा लाभ होगा। आरबीआई के बूस्टर डोज का असर ऑटो और रियल्टी स्टॉक पर दिखा। इनमें क्रमशः 1.3 फीसदी और 2.2 फीसदी की तेजी देखी।

वहीं, फार्मा इंडेक्स में 2.3 फीसदी की गिरावट आई। यह इंडेक्स दो सत्रों में 4.9 फीसदी गिर चुका है। अमेरिका ने विदेशी सहायता रोक दी है, जिससे एड्स दवा निर्माताओं पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी फेक्टर का असर दवा कंपनियों के स्टॉक पर दिख रहा है। स्मॉल-कैप और मिड-कैप कमजोर निमाही नतीजों और महंगे वैल्यूएशन के चलते 1.8 फीसदी और 0.5 फीसदी की गिरावट के साथ लगातार लड़खड़ाते रहे।

8वें वेतन के लिए कितना करना होगा

इंतजार, कैसा रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर अपनी मुहर लगाई है। इसके लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। इसका लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। अमूमन वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में 15 से 30 फीसदी तक की वृद्धि की सिफारिश करते हैं। आइए जानते हैं कि 8वां वेतन लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों 2025 खत्म होने तक तैयार कर ली जाएंगी और इन्हें 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म होने वाला है।

बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन कब से मिलेगी?

एस्पर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए पैसे 1 जनवरी से मिलेंगे। अगर किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग को लागू करने में कुछ देर होती है, तो सरकार 1 जनवरी से ही बढ़े हुए पैसे जोड़कर भुगतान करेगी यानी कर्मचारियों को एप्रियर मिलेगा।

सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा?

7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फेक्टर 2.57 था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फेक्टर 2.86 होने की उम्मीद है। इस हिसाब से न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। ज्यादातर एस्पर्ट का अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक वेतन 41,000 से 51,480 रुपये महीना के बीच रह सकता है।

चीनी का बढ़ेगा भाव! गन्ने का उत्पादन घटा, रिकवरी रेट भी न्यूनतम स्तर पर

परिवहन विशेष न्यूज

परिवहन लागत और मजदूरी के साथ अन्य खर्च भी बढ़ें हैं लेकिन गन्ने से चीनी निकलने की मात्रा घट गई है। इसकी सीधी मार किसानों पर पड़ रही है। चीनी मिल संचालक किसानों के गन्ने को कमतर श्रेणी का बताकर मूल्य घटा रहे हैं। किसान लाचार हैं क्योंकि 11 प्रतिशत तक रिकवरी वाली गन्ने की उन्नत प्रजाति 0238 तेजी से बीमारी की चपेट में आ रही है।

नई दिल्ली। प्रतिकूल मौसम एवं बीमारी के चलते गन्ने के उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ चीनी की रिकवरी दर में भी कमी देखी जा रही है। इससे चीनी उद्योग की चिंता बढ़ गई है। किसानों का नुकसान तय है। उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर पड़ सकता है। रिकवरी का आशय गन्ने से चीनी निकलने की दर से है, जो फसल की गुणवत्ता, मौसम की स्थितियों एवं चीनी मिलों के शुरू होने के समय पर निर्भर करता है।

भारत में रिकवरी दर को दस प्रतिशत से ऊपर रहने पर बेहतर माना जाता है, किंतु इस बार कोई रिकवरी दर 8.81 प्रतिशत भी नहीं पहुंचा है। राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी दर 8.81 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी दौरान यह आंकड़ा 9.37 प्रतिशत था। साफ है इस बार अभी तक गन्ने से 0.56 प्रतिशत कम चीनी की प्राप्ति हो रही है।

गन्ने की रिकवरी दर (प्रतिशत में)

| राज्य | 2024-25 | 2023-24 |
|--------------|---------|---------|
| उत्तर प्रदेश | 9.05 | 9.90 |
| हरियाणा | 8.30 | 9.20 |
| मध्य प्रदेश | 8.50 | 9.50 |
| पंजाब | 8.30 | 8.40 |
| उत्तराखंड | 8.70 | 9.20 |
| बिहार | 9.20 | 9.20 |
| महाराष्ट्र | 8.80 | 8.95 |
| कर्नाटक | 8.50 | 9.60 |
| तमिलनाडु | 8.30 | 8.90 |

इसे सामान्य भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि पिछले साल चीनी मिलों तक पहुंचने वाले गन्ने से प्रति

क्विंटल 9.37 किलोग्राम चीनी निकलती थी। इस बार उतने ही गन्ने से मात्र 8.81 किलो चीनी निकल रही है। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने की कीमतें बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति क्विंटल 20 रुपये की वृद्धि हो चुकी है।

परिवहन लागत और मजदूरी के साथ अन्य खर्च भी बढ़े हैं, किंतु गन्ने से चीनी निकलने की मात्रा घट गई है। यह बढ़ा संकट है। इसकी सीधी मार किसानों पर पड़ रही है। चीनी मिल संचालक किसानों के गन्ने को कमतर श्रेणी का बताकर मूल्य घटा रहे हैं। किसान लाचार हैं, क्योंकि 11 प्रतिशत तक रिकवरी वाली गन्ने की उन्नत प्रजाति 0238 तेजी से बीमारी की चपेट में आ रही है। इसका कोई विकल्प भी नहीं है।

12 राज्य गन्ने के प्रमुख उत्पादक

नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे के अनुसार देश में 12 राज्य प्रमुखता से गन्ने का उत्पादन करते हैं। रिकवरी के मामले में इनमें से आठ राज्यों का हाल बुरा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और तेलंगाना को छोड़कर किसी राज्य में रिकवरी दर नी प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की रिकवरी में 0.85 प्रतिशत की गिरावट है। दूसरा महाराष्ट्र है, जहां 0.15 प्रतिशत की गिरावट है। मध्य प्रदेश और हरियाणा की स्थिति भी अधिक खराब है। यहां रिकवरी दर में लगभग एक प्रतिशत की कमी है।

चीनी का MSP पांच साल से स्थिर

चीनी मिल संगठनों का कहना है कि उत्पादन लागत में करीब 150 रुपये प्रति क्विंटल तक वृद्धि हो गई है, जबकि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) पिछले पांच वर्ष के आंकड़े पर स्थिर है। किसानों के घाटे को देखते हुए अगर गन्ने के परामर्श मूल्य में वृद्धि की गई तो चीनी मिलों का घाटा बढ़ जाएगा। इसलिए उनकी मांग चीनी की एमएसपी बढ़ाने की है, लेकिन ऐसा होने पर मिलों और किसानों के नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है, मगर उपभोक्ताओं की जेब ढीली हो सकती है।

